तिब्बत देश

चीन : तिब्बत पर कब्जा, दिलों पर नहीं

पिछले दिनों तिब्बत के लिथांग नगर की एक घटना ने इस बहस को फिर से गर्म कर दिया है कि 56 साल के नियंत्रण के बाद भी चीन सरकार तिब्बती जनता का मन जीतने या उसके मन से तिब्बती आजादी की ललक को मिटाने में किस हद तक कामयाब रही है। लिथांग हर साल अगस्त में लगने वाले खंपा घुड़सवारों के मेले के कारण मशहूर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। 1951 में तिब्बत को जबरन चीन में शामिल करने से पहले लिथांग तिब्बत के खम प्रांत का हिस्सा था ।

इस साल इस मेले के उद्घाटन और चीनी सेना की 80वीं सालगिरह के समारोह को एक साथ एक अगस्त के दिन आयोजित किया गया था। लेकिन समारोह के शुरू होने से कुछ क्षण पहले अचानक ही अधेड़ उम्र का एक तिब्बती किसान रोंग्ये आद्राक समारोह के मंच पर चढ़ गया। उसने पहले तो स्थानीय लिथांग मठ के प्रधान भिक्षु को परंपरागत तिब्बती स्कार्फ भेंट किया और उसके बाद लाउडस्पीकर व्यवस्था का माइक अपने हाथ में लेकर भाषण देना शुरू कर दिया। उसके भाषण का केंद्र बिंदु यह था कि तिब्बत को चीनी गुलामी से मुक्ति चाहिए और तिब्बती जनता को चीनी कब्जे के खिलाफ खड़ा होने का वक्त आ गया है। उसने चीन सरकार से मांग की कि दलाई लामा को तिब्बत यात्रा पर बुलाया जाना चाहिए।

मेले में दूर–दूर के कस्बों और गांवों से आए हजारों तिब्बतियों के लिए यह एक अनापेक्षित लेकिन रोचक अनुभव था। कुछ देर में ही जनता ने उसके भाषण का तालियों और सीटियों से स्वागत शुरू कर दिया। रोंग्ये आद्राक के सुर में सुर मिलाते हुए वहां तिब्बत की आजादी और दलाई लामा के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। तब कहीं जाकर मंच पर बैठे चीनी अधिकारियों को समझ में आया कि तिब्बती भाषा में चल रहे इस भाषण में कुछ गड़बड़ है। अब चीनी पुलिस हरकत में आयी और आद्राक को मंच से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन करने वाली भीड़ ने आद्राक की रिहाई के लिए स्थानीय पुलिस थाने का घेराव भी किया। (समाचार 12–13 पृ पर) । पिछले समाचारों तक आद्राक अभी भी पुलिस हिरासत में हैं और स्थानीय तिब्बतियों में इसके खिलाफ असंतोष जारी है।

इस बीच तिब्बत के बाहर काम कर रहे तिब्बती संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने आद्राक की रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया है। तिब्बत पर किसी भी कीमत पर अपना कब्जा बनाए रखने को आतुर चीन सरकार आसानी से इस आंदोलन के दबाव मे आकर कोई फैसला करेगी, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ साल में चीन सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के दबाव में आकर दस से ज्यादा तिब्बती स्वतंत्रता संग्रामियों को रिहा करके और उन्हें तिब्बत से बाहर जाने की अनुमति देकर यह दिखा चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे झुका सकता है। लेकिन यह भी सच है कि पंचेन लामा और तेनज़िन देलेक जैसे नाजुक मामलों में वह अमेरिका समेत कई सरकारों और यूरोपीय संसद के दबाव को दरकिनार करती आ रही है।

रोंग्ये आद्राक 52 साल का एक सामान्य बंजारा किसान है जिसने अपनी जिंदगी में आजाद तिब्बत का कभी स्वाद नहीं चखा। वह आजादी और लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा भी नहीं जानता। वह पिछली तीन पीढ़ियों के उन तिब्बतियों में से है जो गुलाम तिब्बत में पैदा होकर चीनी प्रोपेगेंडा के बीच बड़ी हुई हैं। ऐसे में एक अनपढ़ बंजारे तिब्बती के मन में तिब्बती आजादी की यह ललक यह दिखाती है कि तिब्बत के भीतर आजादी की अलख बुझी नहीं है। कुछ दिन पहले निर्वासन से प्रकाशित होने वाली मासिक वीडियो–पत्रिका 'बोड–ग्यालो' का ताजा अंक देखते हुए मुझे उसमें आद्राक की दो किशोर बेटियों के इंटरव्यू देखने को मिले। ये लड़कियां उन हजारों तिब्बती बच्चों में से हैं जिन्हें तिब्बत में रहने वाले उनके माता पिता ने इस उम्मीद से नेपाली तस्करों के हाथ भारत भेज दिया है कि वे गुलामी के माहौल से बाहर जा सकें और तिब्बती निर्वासन सरकार के स्कूलों में पढ़कर अच्छे तिब्बती नागरिक बन सकें। वे भारत के एक तिब्बती स्कूल में पढ़ रही हैं। इसमें उनकी बड़ी बेटी रुलाई भरी आवाज में बता रही थी कि किस तरह उसके पिता तिब्बत के लिए कुछ कर गुजरने को छटपटाते रहते थे।

कुछ साल पहले काठमांडू में मेरी मुलाकात तकरीबन 35 वर्षीय एक तिब्बती से हुई जो अपनी बेटी को वहां के तिब्बती स्कूल में दाखिल कराने के बाद तिब्बत वापस जाने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जिंदगी में दोबारा अपनी बच्ची से मिल भी पाएगा या नहीं। तिब्बत में चीन सरकार से पासपोर्ट और नेपाल जाने की अनुमति पाने के लिए उसने और उसकी पत्नी ने अपने कुछ याक और भेड़ें बेचकर चीनी अफसरों की रिश्वत का जुगाड़ किया था। बच्चे को तिब्बत से बाहर भेजने का कारण पूछने पर उसने जो किस्सा सुनाया वह तिब्बत की असलियत बयान करने को काफी था। स्थानीय चीनी स्कूल में दाखिल कराने के एक हफ्ते के भीतर ही बच्ची ने एक दिन घर आकर कुहराम मचा दिया। घर के मंदिर में रखी दलाई लामा की फोटो को घर से बाहर फेंकने का आग्रह करते हुए वह मां–बाप को बता रही थी कि ''दलाई लामा गद्दार है। वह हमारे देश चीन का दुश्मन है। स्कूल टीचर कहती है कि ऐसे आदमी की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए।'' चीनी शिक्षा के इस रूप से पति–पत्नी को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें बच्ची के लिए क्या करना है।

चीन की सरकारी प्रोपेगेंडा मशीनरी आज दुनिया को यह बताने में कोई कसर नहीं उठा रखती कि तिब्बत द्वारा चीन में 'अपनी मर्जी से शामिल' होने के बाद वहां खुशहाली है और लोग चीनी शासन से खुश हैं। इसमें भी शक नहीं कि आज के तिब्बत में चीन से आजादी पाने या दलाई लामा के समर्थन में सार्वजनिक नारेबाजी या प्रदर्शन की घटनाएं केवल इक्का दुक्का ही हो पाती हैं। हर गली और घर पर खुफिया नजरें रखने वाली चीनी गेस्टापो 'पी एस बी' से डरे तिब्बती नागरिक ऐसी हिम्मत दिखाने से अब डरते हैं।

उन्हें 1959 की मार्च के वे दिन याद हैं जब ल्हासा से शुरू हुए आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए चीनी सेना ने 80 हजार से ज्यादा तिब्बतियों को गोली से उड़ा दिया था। वे 1988 के उस ताजा अनुभव को भी नहीं भूले हैं जब ल्हासा में उठे तिब्बती जन उभार को तिब्बत के तत्कालीन चीनी गवर्नर हू जिन ताओ ने चीनी सेना के टैंकों से कुचल डाला था। हू की इसी 'शानदार सफलता' के तिब्बती माडल को इस्तेमाल करके चीन सरकार ने कुछ महीने बाद बीजिंग के तिएन अनमन छात्र आंदोलन को कुचलने में सफलता पायी थी। दमन के इसी हू–माडल के कारण तब देंग जिआओ पिंग ने हू जिंताओ को ईनाम देकर चीन की उस सत्ता सीढ़ी पर बिठाया था जहां से वह राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं।

लेकिन यह भी सच है कि तिब्बत पर विदेशी चीनी शासन के खिलाफ आम तिब्बती नागरिक के मन के भीतर आज भी पहले जैसा गुस्सा सुलग रहा है। यह गुस्सा आए दिन कभी किसी दीवार पर आजादी समर्थक नारों के रूप में दिखाई देता है, कभी किसी मठ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के प्रदर्शन के रूप में और कभी एक अनगढ़ ग्रामीण रोंग्ये आद्राक के उस दुस्साहसी भाषण के रूप में जिस पर आम तिब्बती चीनी पुलिस थानों को घेराव कर बैठते हैं। रेडियो, इंटरनेट और बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के कारण अब तिब्बती जनता को सच्चाई पता चलने लगी है और बाहरी दुनिया को तिब्बत के भीतर सुलगती आजादी की आग की जानकारी मिलने लगी है। ऐसे में भला चीनी उपनिवेशवाद वहां पर कब तक अपने दमन और का झूठ के सहारे टिका रह सकेगा?

— विजय क्रान्ति

नाथु–ला सीमा पर भारतीय व्यापारियों के साथ चीनी सैनिक : असली इरादे ?

पहले भारत–विरोध, फिर माल बेचने के लिए चीन ने रुख बदला

अरबों डालर के भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से ललचाए चीन की नजर अब भारतीय बाजार पर

भारत के परमाणु कार्यक्रम का चीन हमेशा विरोध करता रहा है और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत बनाता रहा है। पर अब भारत के परमाणु बाजार में अपने व्यापारिक हित साधने के लिए चीन ने उलटा राग भी गाना शुरू कर दिया है।

भारत–अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर चीन ने जो दोमुंहा रवैया अपनाया है उसे देखकर विशेषज्ञ हैरान हैं। पहले तो भारत के परमाणु कार्यक्रम का चीन हमेशा विरोध करता रहा है और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को भारत के खिलाफ मजबूत बनाता रहा है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां भी अपने आका चीन सरकार के इरादों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ महीने से भारत–अमेरिका समझौते को पटरी से उतारने के लिए इस समझौते को रद्द करने का अभियान पूरे जोर शोर के साथ चलाती आ रही हैं। पर अब भारत के परमाणु बाजार में अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए चीन ने उसी सांस में उलटा राग भी गाना शुरू कर दिया है। समाचारों के अनुसार चीन सरकार ने कहा है कि वह भारत के परमाणु कार्यक्रम में सहयोग देने को तैयार है।

अखबारों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार चीन ने कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा मानकों के अनुसाार परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सभी देशों से सहयोग करने को तैयार है। चीन के इस बयान से जाहिर है कि चीन भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम में अरबों डालर के संयंत्रों की खरीद को भी अपने हाथ में रखना चाहता है।

उल्लेखनीय है कि भारत–अमेरिका समझौते के तत्काल बाद चीन की सेंट्रल कमिटी के मुखपत्र ' पीपल्स डेली' ने लिखा था कि समझौते से भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग का नया दौर शुरू होता है। इस सहयोग का भारत–अमेरिका संबंधों तथा दक्षिण एशिया पर असर पड़ेगा।

लेख में चीन सरकार की खीज प्रकट करते हुए कहा गया था कि अमेरिकी परमाणु उर्जा कानून, परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को परमाणु टेक्नालाजी या असैनिक कार्यक्रम के लिए सप्लाई की गई नई मगर सैनिक कार्यक्रम में इस्तेमाल हो सकने वाली प्रौद्योगिकी की आपूर्ति पर रोक लगाता है। और कि अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु सहयोग के लिए दोहरे मापदंड दिखाकर दुनिया को खतरे का संकेत दिया है। ऐसा करते हुए चीन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने प्रभाव को कम किया है।

वहीं अगस्त के आखिर में जब भारत के 11 सदस्यीय एमिनेंट पर्सस ग्रुप या ईपीजी ने बीजिंग में विदेश मंत्री यांग जियेशी से मुलाकात की तो जियेशी ने उनसे कहा कि चीन आईएईए के नियमानुसार परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के क्षेत्र में हर देश के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशने को तैयार है। यह जानकारी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सूत्रों ने एक संवाद समिति को दी।

यांग ने तो चीन – भारत के बीच संभावित असैन्य परमाणु सहयोग के बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन गत वर्ष राष्ट्रपति हू चिंताओ की भारत यात्रा के दौरान दोनों सरकारों की ओर से इस आशय के संकेत मिले थे। हू की यात्रा के दौरान जारी बयान में कहा गया था कि भारत और चीन दोनों के लिये असैन्य परमाणु उर्जा कार्यक्रम का विस्तार उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की निजी राष्ट्रीय उर्जा योजनाओं का महत्वपूर्ण तत्व है इसलिये दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से परमाणु उर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को सहमत हैं।

ईपीजी की इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व पूर्व राजदूत सीवी रंगराजन ने किया जबकि चीनी प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई पूर्व उप विदेश मंत्री लियु शुकिंग कर रहे थे। यांग ने आश्चर्यजनक रूप से भारत के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने की बात नहीं की। ईपीजी के बैठक के नतीजे पर टिप्पणी करते हुए भारत में चीन के पूर्व राजदूत चेंग रुइशेंग ने कहा कि दोनों पक्षों ने इसका इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी के लिए किया।

लेकिन भारत– अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते

के तुरंत बाद भारतीय समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित हुई थीं उनका सार था कि चीन ने पाकिस्तान के साथ परमाणु उर्जा सहयोग के लिये पींगें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। इस आशय के एक लेख में कहा गया कि भारत–अमेरिका के बीच परमाणु उर्जा समझौते की बात शुरू होते ही चीन ने भी गत साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ ऐसा ही समझौता कर लिया।

बीजिंग से आये एक अन्य समाचार के अनुसार हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण से संबंधित एक प्रमुख चीनी विचारक ने आज यहां कहा कि चीन, भारत के साथ आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश सकता है।

चाइना आर्म्स कंट्रोल एंड डिसार्मामेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ रिसर्च फेलो जाई दीक्वान ने कहा, ' ऐसी संभावना है कि चीन और भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी के अधीन परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत पाकिस्तान के साथ ऐसा कर चुका है और ऐसी पहल भारत के साथ भी की जा सकती है।'

चीन द्वारा भारतीय सेना का मजाक

नई दिल्ली। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध अखबार ' ग्लोबल टाइम्स' ने भारतीय सेना पर अप्रिय टिप्पणियां की हैं। एक तरफ तो भारतीय सेना को 'एशिया में सर्वाधिक सक्रिय' बताते हुए इशारा किया गया है कि भारत के इरादे आक्रामक हैं वहीं दूसरी ओर इसे 'बुजदिल' बताते हुए कहा है कि भारतीय सैनिकों को 'युद्धबंदी बनने में शर्म नहीं आती।'

समाचार पत्र ने 1962 में भारत पर चीन के हमले का सीधे साधे जिक्र नहीं किया है लेकिन उसके इशारे बिलकुल साफ हैं। इस युद्ध में चीन ने भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था जिसमें ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारी शामिल थे।

बुद्धिजीवियों और विद्वानों में खासे लोकप्रिय माने जाने वाले इस अखबार ने लिखा है बेशक भारतीय सेना आज एशिया में सर्वाधिक सक्रिय है। इस सेना की ताजिकिस्तान में कथित तैनाती है और अफ्रीका में निगरानी केंद्र स्थापित किए गये हैं। इसके अलावा यह सेना बंगाल की खाड़ी में विमान वाहक पोत भेज रही है। लेख में कहा गया है कि भारतीय सेना रोज न रोज कोई न कोई खबर बनाती है लेकिन बाहरी दुनिया में इसकी जानकारी कम है।

सिक्किम में भारतीय सेना के दो बंकरों पर दावा ठोका चीन ने

चीन ने भारत पर नया दबाव बनाते हुए मांग की है कि भारत सिक्किम सीमा पर बने दो बंकरों को खाली कर दे। चीन ने दावा किया है कि ये बंकर उसकी जमीन पर बने हैं। भारत ने कई साल पहले ये बंकर अपनी जमीन पर बनाये थे। चीन ने पहली बार अचानक इन्हें चुनौती दी है। इसलिए पर्यवेक्षकों को चीन के इस रुख पर आश्चर्य हो रहा है।

चीन ने सिक्किम को भारत का अंग मान लिया है। लेकिन सिक्किम सीमा पर इस मसले को फिर से छेड़े जाने को लोग भारत–अमेरिका सामरिक तालमेल से भी जोड़ रहे हैं। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि ये दोनों बंकर सिक्किम, बंगाल और भूटान के त्रिकोण पर हैं।

सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा की वास्तविक नियंत्रण रेखा के अस्पष्ट होने की आड़ में चीन ने ये सवाल उठाए हैं।

चीन गत कुछ वर्षों से अरूणाचल प्रदेश के तावांग इलकों में भी अपने अतिक्रमण को यह कह कर सही ठहराता रहा है कि वहां नियंत्रण रेखा अस्पष्ट है इसलिए निश्चित दावा नहीं किया जा सकता कि कौन सा इलाका किस देश की सीमा के भीतर है। सीमा विवाद के हल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन और चीनी विदेश उपमंत्री ताई पिंग क्वा के बीच बातचीत अब चीन के कड़े रुख के कारण ही अटकी हुई है। भारत और चीन इस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर परस्पर भरोसा कायम करने के लिए अक्सर राष्ट्रीय दिवसों पर ध्वज बैठकें करते रहते हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं।

लेकिन गत 15 अगस्त को जब सिक्किम के नाथुला इलाके में दोनों सेनाओं के ब्रिगेडरों की ध्वज बैठक हुई तो चीन की मिठाई के साथ कुछ कड़वड़ाहट भी आई। चीन ने इस बैठक में सिक्किम की सीमा में भारतीय थलसेना के दो बंकरों का मामला उठाया।

उक्त बैठक में नाथु ला से होने वाले व्यापार की सुरक्षा और इससे जुड़े प्रोटोकाल के मसलों के अलावा सीमा प्रबंध तथा डाक के आदान–प्रदान पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार चीन ने इन बंकरों को हटाने की कोई समय सीमा नहीं दी है लेकिन वह इस तरह की मांग कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। इसे भारतीय सैनिकों के इस आरोप का जवाब भी माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है।

चीन ने भारत पर नया दबाव बनाते हुए मांग की है कि भारत सिक्किम सीमा पर बने दो बंकरों को खाली कर दे। चीन ने दावा किया है कि ये बंकर उसकी जमीन पर बने हैं। भारत ने कई साल पहले ये बंकर अपनी जमीन पर बनाये थे। चीन ने पहली बार अचानक इन्हें चुनौती दी है। इसलिए सैन्य पर्यवेक्षकों को चीन के इस रुख पर आश्चर्य हो रहा है।

बीजिंग–ओलंपिक के खिलाफ बीजिंग के एक पुल पर तिब्बत समर्थक प्रदर्शन : सरफरोशी

खेलों की तैयारी में ओलंपिक की मूल भावना से खिलवाड़ कर रहा है चीन

तिब्बत की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों ने बीजिंग ओलंपिक का लाभ उठाने के लिए कमर कसी

ओलंपिक खेलों की तैयारियों में श्रमिकों को जबरन रोककर उनसे काम लेने और वेतन नहीं देने का मामला हो या पत्रकारों की आजादी को प्रतिबंधित का मुद्दा, विवाद चीन का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं।

चीन इन दिनों अगले साल बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इन खेलों के आयोजन में एक साल से भी कम समय बचा है और उद्घाटन समारोह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह अलग बात है कि ओलंपिक खेलों की तैयारियों में श्रमिकों को जबरन रोककर उनसे काम लेने और वेतन नहीं देने का मामला हो या पत्रकारों की आजादी को प्रतिबंधित का मुद्दा, विवाद चीन का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तिब्बत की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए ये खेल आयोजन एक ऐतिहासिक अवसर की तरह आये हैं। इस आयोजन के कारण पूरी दुनिया का ध्यान चीन पर लगा हुआ है। इसलिए इसका लाभ उठाते हुए तिब्बत की स्वतंत्रता तथा चीन और तिब्बत में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों ने कमर कस ली है। प्रस्तुत रिपोर्ट में इन गतिविधियों का परिचय दिया गया है।

तिब्बती कार्यकर्ता का बीजिंग दौरा

बीजिंग ओलंपिक खेलों के आयोजन के इस अवसर को चीन सरकार एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा अभियान के लिए इस्तेमाल करने में जुटी है। तिब्बत की आजादी के लिए संघर्षरत अंतर्राष्ट्रीय छात्र संगठन 'स्टूडेंट्स फॉर फ्री टिबेट' की तिब्बती कार्यकर्ता और इसके निदेशक सुश्री ल्हादोन टेथांग ने तिब्बत से जुड़े चीनी ओलंपिक प्रोपगेंडे का खुलासा करने के लिए बीजिंग का दौरा किया। अंतरराष्ट्रीय तिब्बत आंदोलन में उनका काफी नाम है। तिब्बत समर्थकों का कहना है कि चीन सरकार ओलंपिक का इस्तेमाल तिब्बत पर अपने अवैध कब्जे को वैध ठहराने के लिए कर रही है। इसके अलावा वह मानवाधिकार संबंधी अपने खराब रिकार्ड के बावजूद विश्व मंच पर एक चीन को एक नेता के रूप में खड़ा करने में जुटी हुई है।

जैसे जैसे चीन ने ओलंपिक तैयारियों को तेज किया है, दुनिया भर के तिब्बत समर्थक लोगों और संगठनों ने चीन तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी पर तिब्बत के मुद्दे पर ध्यान देने का दबाव डालना शुरू कर दिया है। टेथांग ने अपने बीजिंग दौरे की रिपोर्टें अपने ब्लाग 'बीजिंगवाइडओपेन डाट ओर्ग' पर अपनी रिपोर्टों को प्रकाशित किया है।

उन्होंने अपने ब्लाग में लिखा : ''मैंने उस देश के ह्रदय स्थल का दौरा किया जिसने 50 साल से मेरी मातृभूमि को कब्जाया हुआ है। ..यह चीनी सरकार तिब्बत पर कब्जे की क्रूरता के प्रति दुनिया को अंधा करते हुए ओलंपिक के आयोजन को चमकाना चाहती है। हम यह नहीं होने देंगे। हमें बोलना ही होगा और लड़ना होगा। हमें हर मोड़ पर उन्हें चुनौती देनी होगी ..इसलिए मैं यहां हूं।''

एसएफटी के तेनजिन दोरजी ने कहा है कि आईओसी को चीनी अधिकारियों को ओलंपिक का इस्तेमाल दुनिया में यह झूठा संदेश फैलाने के लिए नहीं करने देना चाहिए कि चीन एक मुक्त तथा खुला समाज है तथा चीन के शासन में तिब्बती खुश तथा संपन्न हैं।

उन्होंने कहा कि तिब्बतियों का ओलंपिक सपना अगस्त 2008 तक आजादी पा लेना है और हम आईओसी तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह इसे अमली जामा पहनाने में हमारी मदद को आगे आये।

उल्लेखनीय है कि दोरजी तथा चार अन्य अमेरिकी नागरिकों ने 25 अप्रैल के दिन तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के आधार शिविर पर चीन की ओलंपिक मशाल को एवरेस्ट शिखर पर ले जाने की प्रस्तावित योजना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था।

'टीम तिब्बत' ओलंपिक में शामिल हो

तिब्बतियों ने अपनी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया है और आईओसी से आग्रह किया है कि ' टीम तिब्बत' को अगले साल होने वाले ओलंपिक

खेलों में शामिल होने का न्योता दिया जाये। नवगठित नेशनल ओलंपिक कमिटी टिबेट ने तीन अगस्त को आईओसी के अध्यक्ष जैक्स रोग को पत्र लिखा है। इसमें आग्रह किया गया है कि बीजिंग ओलंपिक में 'टीम तिब्बत' को भेजने का न्योता दिया जाए।

इस समिति का गठन 30 जुलाई 2007 को किया गया। समिति के अध्यक्ष वांग्पो टेथांग ने कहा, ''हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पास अनेक युवा तिब्बती धावकों का समूह है जो अगले साल के खेलों में भागीदारी को लेकर उत्साहित है। इसीलिए हमने तिब्बत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति गठित करने का फैसला किया है। समिति के बोर्ड को विश्वास है कि आईओसी के प्रतिनिधि तथा दुनिया भर की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उसकी मांग का समर्थन करेंगी ताकि वह भी ओलंपिक परिवार का हिस्सा बन सके। फिलहाल तिब्बत एक देश के रूप में ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकता।''

चीन ने 1950 से तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। तिब्बती लोग तभी से चीन के क्रूर शासन के अधीन जी रहे हैं। 'टीम तिब्बत' के सदस्यों में निर्वासन में जी रहे तिब्बती युवा शामिल हैं।

समानांतर ओलंपिक मशाल की योजना

ताइवान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तीन अगस्त के दिन घोषणा की है कि वे चीन के मानवाधिकार अपराधों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अगले सप्ताह समानांतर ओलंपिक मशाल दौड़ शुरू करेंगे।

इस मशाल को 100 शहरों में ले जाने की योजना है। उनका कहना है कि वे विषेश रूप से तिब्बतियों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर चिंतित हैं।

ओलंपिक की तैयारियों के साथ ही सक्रिय हुए विरोधी

चीन में ओलंपिक खेलों के एक साल की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही दुनिया भर के चीन विरोधी संगठन भी एकजुट होने लगे है। मानवाधिकार या तिब्बत की आजादी का समर्थन करने वाले ये संगठन इस आयोजन का इस्तेमाल चीन को बदलने के लिए करना चाहते हैं। ओलंपिक खेलों की 'वन ईयर काउंटडाउन' की शुरुआत आईओसी के अध्यक्ष जैक्स रोगे ने बीजिंग के थियानमेन चौक में एक भव्य समारोह में की। लेकिन इससे एक दिन पहले ही चीन की दीवार पर तिब्बत समर्थकों के एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दल ने ओलंपिक से जुड़ा 42 वर्ग मीटर का एक विशाल बैनर लहराया जिस पर बीजिंग–ओलंपिक

8 अगस्त को चीन की दीवार पर विशालकाय तिब्बत समर्थक बैनर : चोर के घर में सेंध

के खिलाफ चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नारा 'एक दुनिया, एक स्वप्न, मुक्त तिब्बत 2008' लिखा हुआ था। इससे पहले कि चीनी सुरक्षा कर्मियों को इसकी खबर मिलती यह बैनर कई घंटे तक दीवार पर लगा रहा और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता रहा। बाद में चीनी अधिकारियों ने इन छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयार्क स्थित एसएफटी ने बताया कि उक्त छह लोगों में से दो कनाडा के वैनकूवर के हैं। संगठन का कहना है कि इन लोगों की रिहाई के प्रयास किए जा रहे हैं। तिब्बत की आजादी के लिए मांग करने वाले कार्यकर्ता नये सिरे से सक्रिय हुए हैं।

मीडिया की आजादी पर चीनी अंकुश

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक ताजा रपट में कहा है कि चीन ओलंपिक खेलों की मूल भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। इसके अनुसार चीन सरकारन ने अपने राजनीतिक तथा धार्मिक विरोधियों की निगरानी और उन पर कड़ाई बढ़ा दी है। इसके अलावा पत्रकारों को भी जेल भेजा गया है।

एक अन्य संगठन ह्यूमन राइट्स वाच ने भी हाल ही में कुछ ऐसे ही आरोप चीन सरकार पर लगाए थे। वाच का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को मानवाधिकार संबंधी रिकार्ड सुधारने और मीडिया स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के आश्वासन के बावजूद चीन सरकार लगातार पत्रकारों के अधिकारों का हनन कर रही है। इसका कहना है कि चीन में पत्रकार पुलिस के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के लगातार शिकार हो रहे हैं।

तिब्बत की आजादी के लिए मांग करने वाले कार्यकर्ता नये सिरे से सक्रिय हुए हैं। साथ ही मीडिया के लिए अधिक आजादी की मांग भी उठ रही है। इसके अलावा मानवाधिकार के मामले में चीन का रिकार्ड भी निशाने पर है।

फिलाडेल्फिया में मार्च के समापन समारोह में ताकत्सेर रिंपोछे : आस्था की ताकत

तिब्बत की आजादी के लिए मार्च में शामिल हुए ताकत्सेर रिंपोछे

खराब स्वास्थ्य के बावजूद पदयात्रियों की अगुवाई की

यह पदयात्रा मैनहटन स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास से शुरू हुई। इसकी शुरुआत पर एक पत्र जारी किया गया जिसमें चीन की सरकार से तिब्बत, दक्षिण मंगोलिया तथा पूर्वी तुर्किस्तान का अधिग्रहण समाप्त करने का आग्रह किया गया।

तिब्बत की पूर्ण आजादी की अलख जगाने वाले विद्वान और दलाई लामा के बड़े भाई प्रोफेसर ताकत्सेर रिंपोछे ने 27 जून को न्यूयार्क स्थित चीन के वाणिज्य दूतावास से फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस हाल तक 'तिब्बत की आजादी के लिए मार्च' की शुरुआत की। यह पदयात्रा 100 मील की थी और 4 जुलाई को पूरी हुई। इस अवसर पर उनकी पत्नी कुंचोक नोरबू भी उनके साथ थीं। अंतरराष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति अभियान के 25 सदस्यों ने भी इस मार्च में भाग लिया जिन्होंने तिब्बत की आजादी संबंधी नारों की टीशर्ट पहन रखीं थी और हाथों में तिब्बत के झंडे लिए हुए थे।

तिब्बत के वर्तमान इतिहास में ताकत्सेर रिंपोछे का महत्वपूर्ण स्थान है। 1949 में जिस समय चीनी सेना ने तिब्बत के पूर्वी प्रांतों खम और आम्दो पर कब्जा किया उस समय वह आम्दो में कुंबुम मठ के प्रधान थे। चीनी कम्युनिस्ट अधिकारियों ने उन पर भारी अत्याचार करने के बाद उन्हें दलाई लामा की हत्या करने के लिए ल्हासा भेजा था। लेकिन ल्हासा में वह दलाई लामा को चीन के उपनिवेशवादी इरादों की चेतावनी देने के बाद निर्वासन में चले गए। बाद में अमेरिका में बस कर एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए।

27 मुख्य पदयात्रियों वाली इस तिब्बत मुक्ति पदयात्रा के पूरा होने पर उन्होंने कहा कि वह चीनी सरकार से तिब्बत को आजाद करने की मांग करने वाली आवाज का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत को भी आजादी मिले ताकि एक दिन वह अपना स्वाधीनता दिवस मना सके।

यह यात्रा मैनहटन स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास से शुरू हुई। इस यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसमें चीन सरकार से तिब्बत, दक्षिण मंगोलिया तथा पूर्वी तुर्किस्तान का कब्जा समाप्त करने का आग्रह किया गया था। यह यात्रा चार जुलाई को फिलाडेल्फिया में समाप्त हुई जहां तेकत्सर रिंपाछे ने दो ब्लाक तक मार्च करने वालों का नेतृत्व किया। रिंपोछे ने आईटीआईएम के 13 पदयात्रियों तथा साइकिल यात्रियों की उत्तरी अमेरिकी में निकाली गई रैली का भी नेतृत्व किया था। आईटीआईएम के पदयात्रियों तथा बाइकर्स ने 3,330 मील की दूरी 330 से अधिक दिनों में पूरी की थी।

फिलाडेल्फिया के अस्सी साल के गेशे मोनलम ने इस यात्रा के अंतिम दिन पांच मील की दूरी मुक्ति यात्रियों के साथ तय की। वायस आफ अमेरिका की तिब्बती सेवा के एक टीवी रिपोर्टर ने लगभग पूरा दिन इस यात्रा को कवर किया। स्थानीय लगभग 30 तिब्बती तथा स्थानीय समर्थक भी रिंपोछे और गेशे–ला के साथ पैदल चले। जैसे जैसे ये लोग इंडीपेंडेंस हाल की ओर बढ़े, यात्रियों के जत्थे ने एक रैली का रूप ले लिया। रैली की शुरुआत टिबेटेन ऐसोसिएशन आफ फिलेडेल्फिया के अध्यक्ष तेंजिन सुलत्रिम द्वारा दिए गए परिचय और इसके बाद प्रार्थना से हुई।

ताकत्सेर रिंपोछे ने सभी मुक्ति यात्रियों को तिब्बत की आजादी की लड़ाई में योगदान की प्रशस्ति के रूप में खातागा (परंपरागत तिब्बती स्कार्फ) प्रदान किया। रिंपोछे की धर्मपत्नी कुंचोक नोरबू ने पदयात्रियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और तिब्बत की आजादी के लिए प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया।

आंदोलन के अध्यक्ष प्रोफेसर लैरी गेरस्टाइन ने इस पैदल यात्रा के बारे में तथा इस दौरान हुए विभिन्न प्रकार के अनुभवों की जानकारी दी। गेरस्टाइन ने इस पैदलयात्रा को इंडिपेंडेंस हाल में समाप्त करने की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले 1996 में रिंपोछे ने रांग्जेन (तिब्बती आजादी) की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इंडिपेंडेंस हाल की यात्रा की थी।

तेंजिंग नीमा तथा तेंजिन वांगचुक ने तिब्बत की आजादी के बारे में दो रैप सांग गाये। इनमें से एक गीत तिब्बती में था जबकि दूसरा अंग्रेजी में। इसके बाद आंदोलन के बोर्ड सदस्य नावांग नोरबू ने 'तिब्बत

की आजादी का घोषणा पत्र' पढ़ा जिसे जमयांग नोरबू ने लिखा है। बाद में इस घोषणा पत्र को अंग्रेजी में भी पढ़ा गया।

रिंपोछे के पुत्र जिग्मे नोरबू ने सभी मुख्य पदयात्रियों को धन्यवाद दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि तिब्बत की आजादी के लक्ष्य को हासिल करने के लिऐ वे अपने पिता के काम को आगे बढ़ायेंगे और इसके लिए जो बन पड़ेगा करेंगे। अपने संबोधन में जिग्मे ने कहा कि उनके पिता इतनी अधिक उम्र में व्हीलचेयर पर होने के बावजूद जब इस तरह के आयोजन में शामिल होते हैं तो तिब्बतियों को इससे तिब्बत की आजादी के लिए सक्रियता से लड़ने का उत्साह मिलता है। पूरी रैली के दौरान भावनात्मक बयार बही और तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारे लगाये जाते रहे। रैली के समापन से पूर्व परम पावन दलाई लामा की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई और तिब्बत का राष्ट्रगान गाया गया।

रैली के समापन में टिबेटन एसोसिएशन आफ फिलोडेल्फिया के अध्यक्ष ने सभी पदयात्रियों को खातागा प्रदान किया। उन्होंने ताकत्सेर रिंपोछे को भी खातागा और लिबर्टी बेल की एक प्रतिकृति भेंट की। पैदलयात्रियों ने कहा कि वे अगले साल फिर और तिब्बत के आजाद होने तक इस तरह की यात्राएं करते रहेंगे।

इस आयोजन के बाद इंडिपेंडेस हाल से जुड़े पार्क रेंजर ने ताकत्सेर रिंपोछे को लिबर्टी बेल दिखाने की अनुमति मांगी। कुछ फोटोग्राफरों तथा एक फिल्ममेकर के साथ रिंपोछे को एक निजी द्वार के माध्यम से भवन में ले जाया गया। बेल के साथ दलाई लामा का भव्य चित्र वहां था। परम पावन दलाई लामा 1990 के दशक की शुरुआत में यहां आये थे। रिंपोछे ने दलाई लामा की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई।

चीन पर पत्रकारों के अधिकारों के हनन का आरोप

न्यूयार्क। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को मानवाधिकार संबंधी रिकार्ड सुधारने और मीडिया स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के आश्वासन के बावजूद चीन लगातार पत्रकारों के अधिकारों का हनन कर रहा है।

इस निगरानी एजेंसी का कहना है कि बीजिंग में अगले साल ओलंपिक खेल होने हैं और एक साल से भी कम समय बचा है। लेकिन वहां पत्रकार पुलिस के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के लगातार शिकार हो रहे हैं। पत्रकार सादे कपड़े वाले उन गुंडों का शिकार हो रहे हैं जो देखने में सरकारी नौकर जैसे लगते हैं।

ह्यूमन राइट्स वाच की सोफी रिचर्डसन ने कहा कि पत्रकारों के साथ दुव्यर्वहार और प्रताड़ना मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित किए जाने की चीन सरकार की प्रतिबद्धता पर भी सवालिया निशान खड़े करती है। रिचर्डसन ने कहा है कि ऐसा लगता है कि स्वतंत्र मीडिया चीन सरकार को दुश्मन नजर आता है। बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर चीन सरकार ने आईओसी को आश्वासन दिया था कि इस आयोजन के दौरान वह मीडिया पर प्रतिबंधों को कम करेगी। चीन ने यह आश्वासन ओलंपिक चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुपालन में दिया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाले देशों को इस अनुच्छेद का अनुपालन करना होता है। आईओसी ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे लगता हो कि चीन में मीडिया को स्वतंत्रता दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि चीन में हाल ही में अनेक ऐसी घटनांए हुई है ं जिनसे स्पष्ट होता है कि वहां मीडिया पर कड़े प्रतिबंध जारी हैं।

रेल सेवा से तिब्बत के आयात के मुकाबले निर्यात दुगना हुआ

ल्हासा, 28 जून सिन्हुआ चिंघाई–तिब्बत रेल सेवा के शुरू होने के बाद दस माह में तिब्बत से विदेश व्यापार 75 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 32.2 करोड़ अमेरिकी डालर हो गया है। तिब्बत तथा शेष चीन के बीच यह पहली रेल लाईन है।

ल्हासा सीमा शुल्क के आंकड़े बताते हैं कि उक्त राशि में से 10 करोड़ डालर आयात तथा 22.2 करोड़ रुपये निर्यात है। ये आंकड़े गत साल एक जुलाई से लेकर इस साल 30 अप्रैल तक के हैं। इनमें क्रमशः 170 प्रतिशत तथा 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि तिब्बत के विदेश व्यापार में यह बढ़ोतरी मुख्यतः चिंघाई–तिब्बत रेलवे लाइन से संभव हुई है। यह रेल लाइन गत वर्ष एक जुलाई को शुरू हुई थी और चिंघाई प्रांत की राजधानी सिनिंग को ल्हासा से जोड़ती है।

ल्हासा सीमा शुल्क के एक अधिकारी ने कहा कि रेल के कारण परिवहन खर्च में कमी हुई जबकि चीन तथा एशियाई देशों और क्षेत्र के बीच जिंसों का आवागमन तेज हुआ है। चिंघाई–तिब्बत रेल लाईन की लंबाई 1,956 किलोमीटर है और यह दुनिया की सबसे उंची रेल लाईन है। शुरू होने के एक साल में इस रेल लाइन से 15 लाख लोगों ने यात्रा की।

ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को मानवाधिकार संबंधी रिकार्ड सुधारने और मीडिया स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के आश्वासन के बावजूद चीन लगातार पत्रकारों के अधिकारों का हनन कर रहा है। बीजिंग में अगले साल ओलंपिक खेल होने हैं पर वहां पत्रकार पुलिस के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के लगातार शिकार हो रहे हैं।

तिब्बत की कहानी

1. 27 जुलाई के दिन दलाई लामा की जर्मन यात्रा के संदर्भ में हांबुर्ग में उस्ताद ज़ाकिर हुसैन,
2. दलाई लामा के जन्म दिन पर क्लेमेंट टाउन, देहरादून में बालकुप्पे फुटबाल क्लब ने दिल्ली
3. लेह, लद्दाख में 14 अगस्त के दिन दलाई लामा जी की यात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों
4. इंग्लैंड की ब्राइटन यूनिवर्सिटी में इस साल के 'बैस्ट स्टूडेंट' पुरस्कार से सम्मानित होने वाली
5. फ्रांस की सालाना विख्यात साइकिल दौड़ 'टुर डे फ्रांस' के दौरान तिब्बत समर्थकों ने तिब्बती
6. कांठमांडू, नेपाल में 7 अगस्त के दिन स्थानीय तिब्बती समाज ने नई दिल्ली में 33 दिन का अ
7. मसूरी के तिबेतन होम्स फाउंडेशन के स्कूली विद्यार्थियों ने नई दिल्ली में आमरण अनशन पर
8. बंगलूर में रहने वाले तिब्बती समाज ने 23 जुलाई के दिन एक दिन के व्रत और प्रार्थना के रा
9. चीन समर्थक और अंग्रेज़ी दैनिक 'द हिंदू' के मालिक–संपादक एन राम को सद्‌बुद्धि देने के
10. चीन में बीजिंग–ओलंपिक के अलोकतांत्रिक और अमानवीय पहलुओं का अध्ययन करने के लि

♦ आंखें देखी

– कैमरे की जुबानी

तिब्बती संगीतकार लोटेन नामलिंग और जान मैकलॉलिन ने संयुक्त कंसर्ट पेश किया।

को हराकर 3–2 से 13वीं 'ग्यालुम छेन्मो'फुटबाल प्रतियोगिता जीती।

ने उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना का आयोजन किया।

ा मैकेनिकल इंजिनियरिंग की तिब्बती छात्रा तेनज़िन थारचिन शोबा अपनी मां के साथ।

ो झंडों के साथ साइकिल सवारों का स्वागत किया।

ामरण अनशन करने वाले अपने साथियों के समर्थन में एक दिन का सार्वजनिक उपवास रखा।

बैठे अपने 14 तिब्बती सहयोगियों के समर्थन में एक दिन का उपवास और प्रार्थन–दिवस मनाया।

स्ते अपने 14 अनशनकारी साथियों को समर्थन व्यक्त किया।

लिए चेन्नई विश्वविद्यालय के 160 तिब्बती विद्यार्थियों ने 31 जुलाई के दिन सामूहिक प्रार्थना की।

ए 'स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट' आंदोलन की निदेशक ल्हाडोन टेथांग ने बीजिंग की यात्रा की।

– सभी चित्रों का परिचय ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में

ताइवान के राष्ट्रपति चेन शुई बियान और ताइवान के तिब्बत समर्थक : साझा दुश्मन

ताइवान को अत्याधुनिक हथियारों की बिक्री के प्रस्ताव से चीन परेशान

अमेरिका के समक्ष विरोध जताया

विभिन्न सरकारी वेबसाइटों में चीनी हैकरों की सेंध का मामला गहराता जा रहा है। अमेरिका और जर्मनी के बाद ब्रिटेन ने चीनी सेना के हैकरों पर अपनी सरकारी वेबसाइटों को हैक करने का आरोप लगाया है।

बीजिंग, 18 सितंबर ताइवान को अत्याधुनिक हथियार बेचने की अमेरिका की योजना से चीन परेशान है और उसने अमेरिका से अपने इस इरादे को त्यागने की मांग की कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जियांग यू ने उक्त हथियार सौदे को अविलंब रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि ताइवान को अत्याधुनिक हथियारों की बिक्री का चीन दृढतापूर्वक विरोध करता है।

जियांग का कहना है कि अगर अमेरिका ताइवान को पी–3 पनडुब्बीरोधी विमान तथा अन्य अत्याधुनिक हथियार बेचता है तो यह चीन–अमेरिका संयुक्त घोषणापत्रों में चीन को दिए गए वचन, विशेषकर उस संयुक्त घोषणापत्र का उल्लंघन होगा जिस पर दोनों देशों ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे।

यहां उल्लेखनीय है कि चीन सरकार कई बार खुले शब्दों में कह चुकी है कि जरूरत समझने पर वह ताइवान सैनिक कार्रवाई करके फिर से चीन में मिला लेगी। 1949 में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने च्यांग काई शेक की सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद च्यांग ने भाग कर ताइवान में अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। तब से चीन और ताइवान के बीच तनाव चल रहा है। चीन से हमले की आशंका को देखते हुए ताइवान ने वर्ष 2008 में अपने रक्षा बजट में 16.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 340 अरब डालर से अधिक करने की योजना बनाई है। ताइवान मंत्रिमंडल ने अगस्त माह में चीन के हमले की आशंका के कारण रक्षा बजट में बढ़ोतरी का यह फैसला किया था। सांख्यिकी विभाग के अनुसार साल 2008 में रक्षा बजट कुल बजट का 20 प्रतिशत से भी अधिक होगा। मंत्रिमंडल ने अगले साल रक्षा बजट के लिये 1601.6 अरब डालर की मंजूरी दी है जो बजट का 20.1 प्रतिशत है। बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय इस राशि को नये हथियारों तथा उपकरणों की खरीद पर खर्च करेगा। इन नये हथियारों तथा उपकरणों में बारह पी–3 सी ओरियन युद्धक विमान तथा अमेरिका निर्मित एफ 16 लड़ाकू विमान शामिल हैं।

चीन, ताइवान को अपना अंग मानता है और उसे काफी समय से अपने देश में मिलाने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर दोनों देशों में खींचतान चल रही है। यह अलग बात है कि रक्षा बजट में इस बढ़ोतरी के बावजूद ताइवान रक्षा मामले में चीन के मुकाबले कहीं पीछे है।

अब ब्रिटिश सरकारी वेबसाइटों में चीनी हैकरों की सेंध

विभिन्न देशों की सरकारों की वेबसाइटों में चीन के हैकरों की सेंध का मामला और गहराता जा रहा है। अमेरिका और जर्मनी के बाद अब ब्रिटेन ने चीनी सेना के हैकरों पर अपनी सरकारी वेबसाइटों को हैक करने का आरोप लगाया है।

इस आशय का समाचार पत्र गार्जियन में छपा है। इसमें एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हैकरों ने ब्रिटिश विदेश विभाग के साथ ही कई दूसरे विभागों की साइटें हैक कर ली हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका ने चीनी सेना पर उसके रक्षा मुख्यालय पेंटागन की वेबसाइट हैकर करने का आरोप लगाया था।

एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि चीनी हैकर यह काम पिछले चार साल से कर रहे हैं। पिछले साल हाउस आफ कामंस का कंप्यूटर सिस्टम भी इसी वजह से बंद हुआ था। लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। इस बीच चीन ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उसने पेंटागन की वेबसाइट को हैक करने के आरोप का भी खंडन किया था और इसे शीत युद्ध की सोच बताया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि वे

पेंटागन की वेबसाइट को हैक करने का मुद्दा चीन के राष्ट्रपति हू चिंताओ के समक्ष उठायेंगे।

अमेरिका में दलाई लामा को सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान देने की अनुमति

वाशिंगटन चीन के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बत के निर्वासित शासक और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को सम्मानित करने के लिए कैपिटल रोटुंडा में समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है। प्रतिनिधि सभा ने इस आशय के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अमेरिका के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का वहां वही रुतबा है जो भारत में 'भारत–रत्न' का है।

दलाई लामा को यह सम्मान 17 अक्तूबर को दिया जायेगा। प्रतिनिधि सभा ने दलाई लामा को कांग्रेस का गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने का प्रस्ताव पिछले साल ही पारित कर दिया था। इस फैसले से चीन सरकार बहुत तिलमिलायी हुई है। चीन ने दलाई लामा को यह सम्मान दिये जाने और 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का जोरदार विरोध किया था और इसकी निंदा की थी।

'मेड इन चाइना' ब्रांड को बचाने की कोशिश

बीजिंग, 25 अगस्त सस्ते माल के जरिए दुनिया भर के बाजारों में छा जाने की मुहिम पर निकले चीन को अब अपने ही गिरेबां में झांककर देखना पड़ रहा है। दुनिया के कई देशों में असुरक्षित होने और अमानवीय मजदूरी के कारण प्रतिबंधित चीनी उत्पादों की सूची हर दिन लंबी होती जा रही है। खाद्य पदार्थों और टूथपेस्ट से शुरू हुआ यह सिलसिला अब टायर, खिलौनों तथा परिधानों तक पहुंच गया है। इससे चिंतित चीन सरकार ने अब गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

खाद्य पदार्थ में जहरीले पदार्थ : गत कुछ सप्ताह में अमेरिका, न्यूजीलैंड और कई अन्य यूरोपीय बाजारों में चीनी कपड़ों, खिलौनों तथा खाद्य पदार्थों में जहरीले पदार्थ पाए गए हैं।

कुछ मामलों में तो चीनी दवा पीकर रोगी की मौत हो गई। इस कारण कई देशों में चीनी उत्पादों पर या तो रोक लगा दी गई है या फिर इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क वालमार्ट भी अपने स्टोरों से चीनी उत्पादों को हटाने की तैयारी में है।

चीन के उपप्रधानमंत्री वू याई इस घटनाक्रम से चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि इससे निपटने के लिए सरकार ने चार माह का अभियान छेड़ा है।

युद्धस्तर पर चलने वाले इस अभियान के तहत उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जायेगा ताकि चीन के उत्पादों पर घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं का भरोसा कायम हो सके।

चीन की एक सरकारी वेबसाइट के अनुसार इस अभियान के तहत जनता के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा का प्रयास किया जायेगा, चीन और उसके उत्पादों की छवि बहाल करने का प्रयास होगा, सख्त राजनीतिक कोशिश की जायेगी तथा दोषी अधिकारियों की नौकरी समाप्त की जायेगी।

तिब्बत में खोजे गए भारतीय जड़ों के नये तार

नई दिल्ली नार्दन सिल्क रूट पर चीन और तिब्बत के सांस्कृतिक स्थलों को कैमरे की निगाह से टटोलने वाले कला इतिहासकार तथा फिल्म निर्माता विनय के बहल के अनुसार तिब्बत और चीन की कई गुफाओं में ऐसी बहुत सी दुर्लभ पेंटिंग हैं जिन पर कश्मीरी कलाकारों के असर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे पता चलता है कि एशिया के इस भूभाग में संस्कृति, कला और धर्म के क्षेत्र में करीबी संबंध रहे हैं।

बहल हाल ही में उत्तरी सिल्क रूट पर चीन और तिब्बत के मुख्य सांस्कृतिक स्थलों की फोटोग्राफी करके लौटे हैं। बहल के अनुसार तुनहुआंग की मोगाओ गुफाओं की कुछ पेंटिंगों पर कश्मीरी कलाकारों का विशेष प्रभाव है। ये गुफाएं चीन की मशहूर बौद्ध कला की प्रतीक हैं। बहल को एशियाई देशों में बौद्ध और हिंदू कलाओं पर विशेष शोध के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिल्क रूट पर 14 हजार किमी में फैले 34 अहम सांस्कृतिक स्थलों के फोटो लिए।

तिब्बत के बारे में बहल कहते हैं कि इस देश के कला इतिहास को समझने के लिए उन्हें बहुत सी जगहें मिलीं। उन्होंने वहां भारतीय कलाकारों का काम देखा। इससे पहले जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यामां, श्रीलंका, भूटान और नेपाल की शुरुआती कलाओं पर अनुसंधान कर चुके हैं। लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के अनुसार 2006 तक वे दुनिया के अलग अलग देशों में 1.60 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं।

चीन के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बत के निर्वासित शासक और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को सम्मानित करने के लिए कैपिटल रोटुंडा में समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है। अमेरिका के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का वहां वही रुतबा है जो भारत में 'भारत–रत्न' का है।

लिथांग घुड़सवारी की तैयारी : चीनी उपनिवेशवाद का खेल

राजनीतिक प्रदर्शन करने वाले तिब्बती की गिरफतारी से विरोध भड़का

चीन के सरकारी वर्षगांठ समारोह में हुआ तिब्बत की आजादी का उद्घोष

आद्राक ने फिर से मंच पर जाकर नारेबाजी जारी कर दी जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हो गए। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस वहां आ धमकी और उसने रोंग्ये आद्राक को गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात स्थान पर ले गई।

मानवाधिकार तथा लोकतंत्र के लिए तिब्बती केंद्र टीसीएचआरडी को मिली पुष्ट जानकारी के अनुसार एक तिब्बती रोंग्ये आद्राक को खम के लिथांग इलाके में राजनीतिक प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लिथांग के इस तिब्बती की गिरफ्तारी एक अगस्त 2007 को हुई जब उसने एक सरकारी सालाना वर्षगांठ के अवसर पर राजनीतिक प्रदर्शन किया। वह एक स्थानीय गांव योउरू का 52 साल का किसान है।

लिथांग काउंटी प्रशासन ने चीन की जनमुक्ति सेना यानी पीएलए के 80वें स्थापना दिवस पर इस समारोह का आयोजन किया था। इस अवसर पर विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद थे जो यह कार्यक्रम तथा हर साल होने वाली प्रसिद्ध घुड़दौड़ देखने के लिए आये थे।

समारोह शुरू होने से ठीक पहले रोंग्ये आद्राक ने अचानक मंच पर जाकर लिथांग मठ के मुख्य लामा लिथांग क्याबगोन को पारंपरिक तिब्बती स्कार्फ पेश किया। उसने वहां लगे लाउडस्पीकर के माइक को अपने नियंत्रण में ले लिया और एक लंबा भाषण दे डाला जिसका मुख्य विषय तिब्बत की आजादी था।

उसने बुलंद आवाज़ में कई नारे लगाए जिनमें से मुख्य नारे थे : 'दलाई लामा को तिब्बत लौटना चाहिए', ' पंचेन लामा को रिहा करो' और ' तिब्बत को आजादी चाहिए'। रोंग्ये ने ने स्थानीय लोगों का आह्वान किया कि वे जल और जमीन के छोटे–छोटे मुद्दों को लेकर आपस में झगड़ना बंद करें। इसके बाद आद्राक मंच से उतरकर सीधे भिक्षु नाग्लू तेंजिन के पास गये और मठ के धार्मिक मामलों को लेकर उन द्वारा अपनाये जा रहे दोहरे रवैये को उजागर किया। यह भिक्षु चीन सरकार के 'देशभक्ति शिक्षा अभियान' में सक्रियता से शामिल है जिसका मुख्य लक्ष्य तिब्बती जनता के मन के चीन के प्रति आस्था पैदा करना है। भिक्षु को यह सब सुनाने के बाद आद्राक ने फिर से मंच पर जाकर नारेबाजी जारी कर दी जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हो गए। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस वहां आ धमकी और उसने रोंग्ये आद्राक को गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात स्थान पर ले गई।

रोंग्ये आद्राक की सुरक्षा को लेकर चिंतित गांव के लोग लिथांग प्रांत कार्यालय गये और अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी देने और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की। इन लोगों ने कार्यालय परिसर में प्रदर्शन भी किया।

सूत्रों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने इन लोगों को डराया धमकाया और उन्हें भगाने के लिए हवा में गोलियां भी चलाई। लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हुई। मामले को गंभीर रूप लेता देख स्थानीय अधिकारियों ने अगले दिन रोंग्ये को रिहा करने का वादा किया। इस पर लोग लौट गये। टीसीएचआरडी ने आद्राक की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संगठन ने रोंग्ये की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद मांगी है।

घुड़दौड़ के भागीदारों पर फर से बने वस्त्र पहनने पर चीन ने जोर डाला

यूशू घोड़ा मेला नाम से मशहूर इस मेले में इससे पहले चीनी अधिकारियों ने घुड़सवारी के करतबों में भाग लेने वालों के लिए एक फरमान जारी किया जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। अधिकारियों ने तिब्बतियों के इस पारंपरिक मेले के घुड़सवारों की भागीदारी के लिए यह शर्त लगा दी कि उन्हें फर वाले कपड़े पहनने होंगे।

इस फरमान ने विवाद पैदा कर दिया क्योंकि कई लोगों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। पिछले साल भारत के अमरावती शहर में कालचक्र पूजा के दौरान तिब्बती जनता से अपील की थी कि वे जंगली जानवरों की हत्या रोकने के लिए उनकी खाल और फर वाले कपड़े पहनने बंद कर दें। तब

रोंग्ये आद्राक : देशप्रेम की ताकत

उन्होंने कहा था कि उन्हें वे फोटो देकर शर्म महसूस हुई है जिसमें चीते या अन्य पशुओं की खाल से बने चोगे पहन रखे हैं। इसके बाद से ही तिब्बत में इस तरह की पोशाकों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई जिससे चीनी अधिकारी जल भुन गये। दलाई लामा की इस अपील के जवाब में पूरे तिब्बत में फर और खाल से बने कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाने का अभियान चल निकला जिसे चीन सरकार ने अपने खिलाफ विद्रोह की तरह लिया। चीन सरकार के यह देखकर सदमा लगा कि दलाई लामा के 48 साल के निर्वासन के बाद भी स्थानीय लोग दलाई लामा में इतनी गहरी आस्था रखते हैं।

द टाइम्स, लंदन का कहना है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों को 3,000 युआन का जुर्माना लगाया गया जो किसी भी आम तिब्बती किसान के लिए बहुत बड़ी राशि है। लिथांग में आद्राक द्वारा सार्वजनिक भाषण देने और स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन के पीछे चीनी आदेश से पैदा हुआ गुस्सा था।

आईसीटी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि उपरोक्त प्रदर्शन के बाद आने वाले समाचारों से पता चलता है कि लिथांग में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कारजे क्षेत्र के इस गांव में भारी संख्या में हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गये हैं जो लोगों की गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। रोंग्ये आद्राक स्थानीय बंजारा समाज के एक लोकप्रिय सदस्य रहे हैं।

इस बीच आईसीटी को मिली सूचना के अनुसार कुछ सप्ताह पहले चीन के अधिकारियों ने लिथांग मठ में एक मांगपत्र जारी करके भिक्षुओं को इसपर हस्ताक्षर करने को कहा था। इस मांगपत्र में कहा गया था कि

आज़ादी का स्वर हैं लिथांग रोंग्ये आद्राक

कर्नाटक में मुंडगोड के द्रेपुंग मठ से रोंग्ये आद्राक के भतीजे रोंग्ये जमयांग का खुला खत

''अगर वह बोलते नहीं तो शायद खबर भी नहीं बनती और चीनी दमन चुपचाप जारी रहता। लोगों के दिल में जो दर्द है वह बना रहता या यूं कहें कि दिल की गहराई में कहीं दबा रह जाता और कभी सुनाई नहीं देता। सब कुछ ऐसे ही 'सामान्य' चलता रहता। 53 साल के एक धार्मिक व्यक्ति लिथांग रोंग्ये आद्राक ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए अपने मन की बात कही और सचाई को बोला। उस सचाई को जो उनके साथी नागरिकों के दिल में कहीं दबी हुई थी या जिसे दबा कर रखा गया था।

एक पिता के रूप में रोंग्ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उनकी भूमिका एक समाज सेवक के रूप में भी है। लिथांग यानी पूर्वी तिब्बत का एक भू भाग। तिब्बत यानी वह देश जिसे चीन ने कब्जा कर लिया और अपना उपनिवेश बना लिया। आज यहां सैन्य शासन है और उसके सभी नियम बीजिंग में बैठे हान समुदाय के शीर्ष अफसरों द्वारा तय होते हैं।

विकास के नाम पर तिब्बत में जो कुछ हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। सड़कों तथा पुलों का जाल वहां लाखों की संख्या में बसाए जा रहे चीनियों की सुविधा के लिए है जो स्थानीय लोगों के पारंपरिक जीवन को तबाह कर रहा है। लिथांग की घटना तो एक अक्तूबर को हुई। वह भी हर साल होने वाली एक घुड़दौड़ के आयोजन के दौरान जब सभी आधिकारिक अतिथि मंच पर उपस्थित थे। रांग्ये आद्राक ने मंच पर पहुंच कर माइक संभाला और एक आश्चर्यजनक बयान दिया। उन्होंने अपने साथी तिब्बती लोगों से छोटे–छोटे मुद्दों पर आपस में नहीं लड़ने को कहा।

उन्होंने सभी तिब्बती लोगों से एकजुट होने को कहा। लोग जब उनके संबोधन पर एकाग्रता से ध्यान दे रहे थे तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या वे चाहते हैं कि दलाई लामा वापस लौटें। इस पर वहां मौजूद लोगों ने सर्वसम्मति से कहा कि हां वे चाहते हैं कि परम पावन दलाई लामा वापस लौटें।

हम आपसे इस अपील के माध्यम से आजादी और न्याय के इस संदेश को फैलाने को आग्रह करते हैं। आप भी चीन की सरकार से रोंग्ये की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की अपील करें। ऐसा आग्रह संयुक्त राष्ट्र तथा आपकी सरकार से भी है।''

– रोंग्ये जमयांग

इस मांगपत्र में कहा गया था कि भिक्षु यह चाहते हैं कि दलाई लामा तिब्बत नहीं लौटें।मठ के भिक्षुओं ने इस मांगपत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इस प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय लोग यह जताना चाहते थे कि सरकारी मांगपत्र झूठा है और वह लिथांग के तिब्बती लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

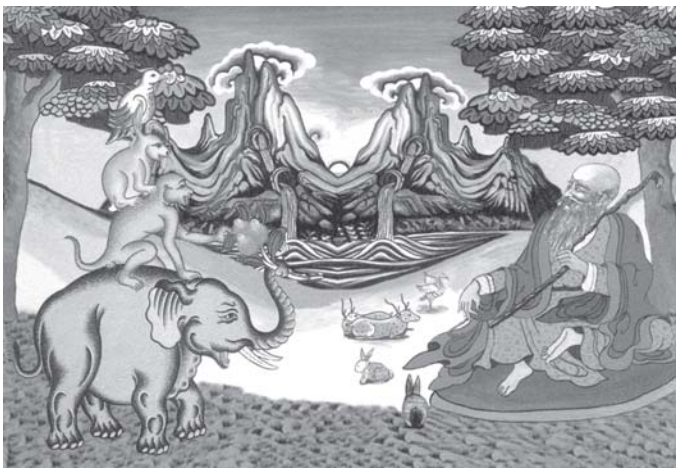

बौद्ध कथाओं में जानवर : सहअस्तित्व का मंत्र

तिब्बत में जारी है अवैध शिकार, संरक्षण के सरकारी प्रयास प्रभावी नहीं

वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर

तिब्बत में वन्य जीवों के शिकार का दौर थम नहीं रहा है। यह सब तिब्बत के बाहर से लाकर बसाए जा रहे चीनी नागरिकों द्वारा दशकों से चले आ रहे शिकार के कारण हुआ है। *मूल्यवान शहतूश ऊन के लिए तिब्बती हिरणों को मारा जा रहा है।*

धर्मशाला (डीआईआईआर के पर्यावरण तथा विकास डेस्क की रिपोर्ट) तिब्बत में जंगली वन्य जीवों के शिकार का दौर थम नहीं रहा है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इस साल की शुरुआत में पश्चिमी एडवेचर्स को 20 से अधिक तिब्बती हिरणों के नये कंकाल मिले। मूल्यवान शहतूश ऊन के लिए इन्हें मारकर इनकी चमड़ी उतार ली गई थी। चीनी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कानून, 1989 में तिब्बती हिरण और चिरू (तिब्बती में 'त्सोई') को श्रेणी एक की संरक्षित प्रजाति में रखा गया है।

इसके बाद बीजिंग सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाये ओर तिब्बती हिरणों की संख्या में हाल ही में कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिली। लेकिन अब भी यह संख्या कुछ खास नहीं है और इस प्रजाति के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। यह सब तिब्बत के बाहर से लाकर बसाए जा रहे चीनी नागरिकों द्वारा दशकों से चले आ रहे शिकार के कारण हुआ है।

चीन ने वर्ष 1990 में इनके शिकार को अवैध घोषित कर दिया था, पर इसके बावजूद इस प्राणी के अस्तित्व पर गहरा संकट बना हुआ है।

दुनिया में तिब्बत उन कुछ क्षेत्रों में शामिल है जहां इसकी अनेक प्रजातियों के विभिन्न जैविक पहलुओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रयोग किए गये हैं। तिब्बत में शिकार ऐतिहासिक रूप से बुरा माना रहा जाता है। पर कुछ गरीब लोग अपनी आजीविका के लिए इस तरह का काम करते रहे हैं पर उसका प्रभाव कम जनसंख्या के कारण नगण्य था। चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से अनेक वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। उनके आश्रय स्थल तबाह कर दिए गये हैं या चीन के जंगली उत्पादों के गैरकानूनी कारोबार या आनंद के लिए शिकार के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए तिब्बत के वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं जिनमें तिब्बती हिरण भी है।

वर्ष 2003 में इस संबंध में चीन सरकार की ओर से जारी श्वेत पत्र में कहा गया था कि तिब्बत से किसी भी प्रजाति के लुप्त होने की बात सही नहीं है लेकिन इसमें स्वीकार किया गया था कि अनेक प्राणी 'लुप्त होने के कगार पर हैं।' तिब्बत पठार पर अब प्राणियों की कम से कम 81 प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें संकटग्रस्त माना गया है।

उक्त प्रजातियों में से 39 स्तनधारी, 37 पक्षी, चार जल और थलचर तथा एक सरीसृप प्रजाति शामिल हैं। चीन ने वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण की पहल तिब्बत में बहुत बाद की जबकि खुद चीन में यह कदम काफी पहले उठा लिए गये थे।

चीन की राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (सेपा) के अनुसार 2000 के अंत तक तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र 'टार' में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के 17 प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र थे। उक्त क्षेत्र चीन के कुल प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र का 40 प्रतिशत है। आम्दो में प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र 50,000 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन टार में इस संबंध में रखे गये कर्मचारियों की कुल संख्या 163 है जो चीन के सभी प्रांतों की तुलना में सबसे कम है।

इस क्षेत्र के प्रख्यात जीव विज्ञानी डा जार्ज बी शेलर ने कहा है कि इन संरक्षित क्षेत्रों में अवैध शिकार को रोकने के लिए रेंजरों, प्रशिक्षित कर्मचारियों, वाहनों तथा प्रवर्तन अधिकारों की कमी है। पठार के जित्सा देगु (चीनी में 'जिउचाइगुउ') क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जॉयंट (विशाल) पांडा का यह एकमात्र सुरक्षित आश्रय स्थल माना जाता है। लेकिन वर्षों से यहां चिड़ियाघर के बाहर मुक्त क्षेत्र में कोई पांडा देखने को नहीं मिला है। वन्यजीवों के सिर और खाल जैसे सजावटी अंगों के लिए उनका अबाध रूप से शिकार जारी है। इन्हें सरकारी मीडिया में लगातार दिखाया जाता है जो चीन के वन्य जीवन सरंक्षण के दावों के बिलकुल विरोधाभासी है।

पश्चिमी एडेंचर्स के एक समूह का कहना है कि जब वे खुनू पर्वत शृंखला के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ गैर–तिब्बती लोगों को देखा जो जीप और बाइकों पर सवार थे और शिकार के लिए तिब्बती हिरण का पीछा कर रहे थे। खुद को तिब्बती दिखाने के लिए उन लोगों ने अपने वाहनों पर तिब्बती मंत्र 'ओम मनी पदमे हुम' लिखवा रखा था। लेकिन पश्चिमी नागरिकों ने पुष्टि की कि ये शिकारी चीनी हान या चीनी मुसलिम थे न कि तिब्बती। यह भी देखा गया है कि ऊपरी गरत्से में अधिकतर दुकानें तथा रेस्त्रां चीनी नागरिकों के हैं और मूल तिब्बती लोग वहां हाशिए पर जा चुके हैं जिससे उनका जीवन कठिन होता जा रहा है। ये चीनी नागरिक दुकानों आदि के कारोबार के साथ अवैध शिकार तथा वन्य जीव उत्पादों के कारोबार में भी लगे रहते हैं।

इस समूह ने कहा कि शिकारियों द्वारा पीछे छोड़े गये पशुओं के अंगों आदि से स्पष्ट है कि किस पैमाने पर शिकार बिना किसी बाधा के जारी है। यह चीन के वन्य जीव संरक्षण के लिए उठाये गये कदमों की विफलता की खुली कहानी है। इसके अलावा यह अनुभव इन निर्दोष प्राणियों के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों से भी रूबरू कराता है। अगर सरकार अपने प्राणियों के संरक्षण के प्रयासों को लेकर गंभीर है तो उसे और कड़े कदम उठाने होंगे।

चीन ने जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का अनुमोदन किया है और हम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसके प्रयासों का स्वागत करते हैं जिनमें नये वन्यजीव कानून को लागू करना शामिल है। लेकिन मौजूदा वास्तविकता में उक्त प्रयास काफी कम दिखते जान पड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चीन इस संबंध में सरकारी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर कदम उठायेगा ताकि उक्त वन्य जीवों को धरती से विलुप्त होने से बचाया जा सके।

एवरेस्ट बेस कैंप : अवैध और गलत कामों का अड्डा

बीजिंग। माऊंट एवरेस्ट का तिब्बत की तरफ का आधार शिविर तमाम तरह के गलत कामों का अड्डा बनता जा रहा है। बीबीसी के अनुसार पर्वतारोही तथा लेखक माइकल कोड्स ने अपनी आने वाली किताब में यह बात कही है।

अमेरिका के इस लेखक का कहना है कि आधार शिविर गांव में वेश्याएं और नशे के तमाम साधन उपब्लब्ध हैं। उन्होंने चिंता जताई कि आधार शिविर तक सड़क निर्माण की चीन की योजना इन समस्याओं को और बढ़ा सकती है।

चीन ने इन आरोपों का खंडन किया है कि वह दुनिया की सबसे उंची चोटी को दूषित कर रहा है। कोड्स की आने वाली किताब ' हाइ क्राइम्स : द फेट आफ एवरेस्ट इन एन एज आफ ग्रीड ' है।

पर्यावरणीय बदलाव से नष्ट हो रही है चीन की तराई भूमि

बीजिंग पर्यावरणीय बदलाव के कारण चीन के कब्जे वाले विशाल चिंघाई–तिब्बत पठार पर तराई भूमि नष्ट हो रही है। यह भूमि तिब्बत और चीन की बड़ी नदियों के बहाव को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। सरकारी समाचार पत्र चाइना डेली की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि वेटलेंड के संकुचन के चलते यांग्त्जी तथा येलो नदियों के बहाव में पहले ही कमी आ चुकी है।

इसमें कहा गया है कि इस भूभाग पर वेटलेंड पिछले 40 सालों में दस प्रतिशत से अधिक लुप्त हो गई है। यांगत्जे नदी के मूल में तो वेटलेंड का क्षरण 29 प्रतिशत तक है। चाइनजी एकेडमी आफ साइंसेज के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में कहा गया है कि यांगत्जी नदी के स्रोत पर छोटी झीलों का लगभग 17.5 प्रतिशत हिस्सा तो पहले ही सूख चुका है।

एकेडमी के एक अनुसंधानकर्ता वांग सुआजेन ने कहा, ' नदियों में जल स्तर और मात्रा को बनाये रखने में वेटलेंड की महती भूमिका है।' उन्होंने कहा कि पठार पर वेटलेंड का नष्ट होना बहुत कुछ ग्लोबल वार्मिंग से सम्बद्ध है। पर्यावरणीय बदलाव के कारण इस क्षेत्र में बारिश की मात्रा भले ही बढ़ी हो लेकिन नदियों के जल स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है । अधिक तापमान के कारण वाष्पन भी बढ़ा है।

तिब्बत के पठार को एशिया की कई बड़ी नदियों का स्रोत माना जाता है। अगर बदलाव के कारण इन नदियों के जलस्तर पर असर पड़ता है तो उसका असर भारत, बांगलादेश समेत एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर दिखेगा।

जून में चीनी सरकारी मीडिया ने एक अन्य अध्ययन के हवाले से कहा था कि बढ़ते तापमान के कारण उत्तर पश्चिमी चीन क सिंकियांग क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ये अब तक 20 प्रतिशत पिघल चुके हैं। इसके कारण बर्फ की पट्टी में 1964 के बाद से लगभग 60 मीटर यानी लगभग 200 फुट तक की कमी आ चुकी है।

इसमें कहा गया है कि इस भूभाग पर वेटलेंड पिछले 40 सालों में दस प्रतिशत से अधिक लुप्त हो गई है। यांगत्जे नदी के मूल में तो वेटलेंड का क्षरण 29 प्रतिशत तक है। चाइनजी एकेडमी आफ साइंसेज के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में कहा गया है कि यांगत्जी नदी के स्रोत पर छोटी झीलों का लगभग 17.5 प्रतिशत हिस्सा तो पहले ही सूख चुका है।

भारत के बदलते बाजार को देखते हुए बदला चीन ने आपना खोल

चीन की गतिविधियां भारत के लिए खतरा

–रहीस सिंह–

भारत–अमेरिका परमाणु समझौते की घोषणा होते ही चीन और पाकिस्तानी दूतावासों के अधिकारी थिंक टैंक की भूमिका में आ गए और इसे हथियारों की होड़ बताते हुए दक्षिण एशिया में सामरिक असंतुलन की चेतावनी देनी शुरू कर दी। ऐसा करते समय चीन यह भूल गया कि खुद उसके पास भारत से कई गुणा अधिक परमाणु हथियार हैं और वह पाकिस्तान को लगातार इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।

एशिया के आर्थिक और सामरिक मामलों पर जब भी कोई शोध या रिपोर्ट प्रकाशित होती है या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई बौद्धिक चर्चा होती है तो भारत और चीन अक्सर केंद्रीय विषय होते हैं। इन चर्चाओं में अधिकांशतः एक विरोधाभास दिखाई देता है, जिसमें एक ध्रुव पर भारत–चीन मैत्री की बात आती है तो दूसरी ओर दोनों देश प्रतिस्पर्धी के रूप में नजर आते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है। अर्थ जगत से जुड़े अध्ययन बताते हैं कि 2025 तक चीन दुनिया का कारखाना होगा और भारत विश्व का कार्यालय। जाहिर है, एशिया की दो ताकतें समानता के आधार पर एक ऐसी बुनियाद रख सकेंगी जिसमें हिंदी–चीनी भाई –भाई जैसे विशेषणों की सार्थकता सिद्ध हो सके। लेकिन गहराई में जाने पर वास्तविकता इससे भिन्न दिखाई देती है।

सच तो यह है कि भारत के उभरते बाजार को देखकर चीन ने भारत के प्रति अपने बाहरी खोल को बदलना जरूरी मान लिया है। यहां पर मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा किए गये अध्ययन का जिक्र करना उचित रहेगा जिसमें कहा गया है कि भारत इस समय दुनिया का 12वां सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और 2025 तक वह वैश्विक उपभोक्ता बाजार में पांचवा स्थान हासिल कर लेगा। इस दौरान भारतीय मध्यम वर्ग में 12 गुना वृद्धि होगी। लगभग 2.30 करोड़ भारतीय, जिनकी संख्या आस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या से अधिक होगी, देश के अमीरतम लोगों में होंगे। ऐसे में चीन सरीखे देशके लिए भारत के बाजार की नितांत आवश्यकता होगी। अक्सर देखा गया है कि भारत जब भी सामरिक क्षेत्र में किसी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का फैसला करता है तो चीन प्रत्यक्ष तौर पर या फिर पाकिस्तान को ढाल बनाकर भारत के विरुद्ध विशुद्ध आलोचक की भूमिका में आ जाता है।

भारत–अमेरिका परमाणु समझौते की घोषणा होते ही चीन और पाकिस्तानी दूतावासों के अधिकारी थिंक टैंक की भूमिका में आ गए और इसे हथियारों की होड़ बताते हुए दक्षिण एशिया में सामरिक असंतुलन की चेतावनी देनी शुरू कर दी। ऐसा करते समय चीन यह भूल गया कि खुद उसके पास भारत से कई गुणा अधिक परमाणु हथियार हैं और वह पाकिस्तान को लगातार इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यहां तक कि एशिया में हथियारों की होड़ के लिए सबसे बड़ा दोषी खुद चीन ही है। इसके बावजूद उसने भारत और अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते की बराबरी करने के लिए पाकिस्तानी यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बढ़ाने में सहयोग के लिए समझौते को व्यावहारिक आकार देने का निर्णय किया है।

जापानी समाचार एजेंसी ने पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग यानी पीएईसी के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पंजाब प्रांत के चश्मा या कुंडियन में बनने वाले परमाणु बिजली कांपलेक्स पर पाकिस्तान फिलहाल प्रारंभिक दो चरणों में दो अरब अमेरिकी डालर खर्च करेगा। उसने यह भी लिखा है कि पीएईसी के अधिकारियों का कहना है कि भारत–अमेरिका परमाणु समझौते की तर्ज पर वाशिंगटन के साथ समझौते के लिए बातचीत के विफल होने के बाद पाकिस्तान ने तय किया गया है कि वह स्वदेशी तकनीक से निर्मित ' दाबित जल परमाणु रिएक्टर' चीन की मदद से लगायेगा।

दरअसल, चीन पाकिस्तान के इस परमाणु उर्जा कार्यक्रम के माध्यम से जो रणनीति अपना रहा है उसके कुछ गौण पक्ष भी हैं। पहला यह है कि भारत–अमेरिका समझौते में यह प्रावधान है कि अमेरिकी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी को भारत के पक्ष में सहयोग के लिए तैयार करेगा। चूंकि चीन भी एनएसजी का सदस्य है इसलिए उसे भी इस पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। ऐसी स्थिति में उसका नकारात्मक रुख भारत–चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिए प्रतिकूल साबित होगा। इसलिए अब उसकी कोशिश यह होगी कि वह अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करे जिससे पाकिस्तान को भी उसी प्रकार की रियायतें मिल सकें जैसी भारत को मिलेंगी। हो सकता है कि चीन यह सब इसलिए कर रहा हो कि एनएसजी भारत की मदद नहीं करे।

चीन के रवैये से यह संभव है कि आस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा जैसे बड़े नाभिकीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ नाभिकीय लेन देन संबंधी भारतीय प्रयास खतरे में पड़ जायें। अब चीन अगर वास्तव में भारत के साथ मैत्री भाव से लबालब है तो फिर वह इस प्रकार का रवैया अपनाकर क्या साबित करना चाहता है? सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एशिया में पनपने वाले आतंकवाद का जनक है। ***(दैनिक जागरण 7 अगस्त, 2007 से साभार)***